



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 270]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 25, 2019/वैशाख 5, 1941

No. 270]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 25, 2019/ VAISAKHA 5, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2019

सं. 33/2019-सीमाशुल्क (नै.टै.)

**सा.का.नि. 326(अ).—**सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 50 के साथ पठित धारा 157 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और शिपिंग बिल (ईलेक्ट्रॉनिक इंटेग्रेटेड डिक्लेरेशन) रेग्युलेशनस, 2011 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गयी अथवा ना की गयी बातों को छोड़ते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा:—

**1. संक्षिप्त शीर्षक, अनुप्रयोग तथा प्रारम्भ.—**(1) इन विनियमों को शिपिंग बिल (ईलेक्ट्रॉनिक इंटेग्रेटेड डिक्लेरेशन एंड पेपरलेस प्रोसेसिंग) रेग्युलेशनस, 2019 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम उन सभी सीमाशुल्क स्टेशनों से माल के होने वाले निर्यात पर लागू होंगे जहां जहां इंडियन कस्टम्स एलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज सिस्टम चालू है।

(3) ये विनियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

**2. परिभाषाएँ.—**(1) इन विनियमों में, जब तक की संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत ना हो,-

(क) “अधिनियम” से अभिप्राय सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) से है;

- (ख) “प्राधिकृत व्यक्ति” से अभिप्राय ऐसे किसी निर्यातकर्ता या उसके द्वारा प्राधिकृत ऐसे किसी व्यक्ति से हैं जिसके पास कस्टम्स ब्रोकर्स लाइसेंसिंग रेगुलेशनस, 2018 के अंतर्गत वैध लाइसेंस हो और इसमें कस्टम्स ब्रोकर का ऐसा कोई कर्मचारी भी आएगा जिसको कि कस्टम्स ब्रोकर्स लाइसेंसिंग रेगुलेशनस, 2018, के अंतर्गत फार्म जी में फोटो पहचान पत्र जारी किया गया हो;
- (ग) “ईलेक्ट्रॉनिक इंटेग्रेटेड डिक्लेरेशन” से अभिप्राय ऐसे व्योरे से है जो कि उस निर्यात माल से संबन्धित जिनका प्रवेश इंडियन कस्टम्स ईलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज सिस्टम में होता हो;
- (घ) “ICEGATE” से अभिप्राय केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड के कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम से है;
- (ङ) “धारा” से अभिप्राय इस अधिनियम की धारा से है;
- (च) “सेवा केंद्र” से अभिप्राय प्रधान आयुक्त या आयुक्त, सीमाशुल्क जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसे स्थान से है जहां पर कि किसी ईलेक्ट्रॉनिक इंटेग्रेटेड डिक्लेरेशन कि डाटा एंट्री की जाती हो;
- (छ) “शिपिंग बिल” से अभिप्राय ऐसे ईलेक्ट्रॉनिक इंटेग्रेटेड डिक्लेरेशन से है जो कि इंडियन कस्टम्स ईलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज सिस्टम के द्वारा स्वीकार किया गया हो और इसके द्वारा इसे एक अद्वितीय संख्या प्रदान की गयी हो और इसमें ईलेक्ट्रॉनिक रिकोर्ड्स और प्रिंटआउटस भी आते हैं।

**स्पष्टीकरण.** – इस उपवाक्य के उद्देश्य से, अभिव्यक्ति “ईलेक्ट्रॉनिक रिकोर्ड्स” का वही अभिप्राय होगा जो इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) में दिया गया हो;

(ज) “समर्थन कार्य दस्तावेज़” से अभिप्राय उस ईलेक्ट्रॉनिक या अन्य किसी भी प्रकार के दस्तावेजों से है जो कि उक्त अधिनियम की क्रमशः धारा 17 और 50 के अंतर्गत निर्यात माल के क्लियरेंस के लिए प्रासंगिक हो।

(ज) ऐसे शब्द और अभिव्यक्तियाँ जिनका प्रयोग इन विनियमों में तो हुआ हो लेकिन वे यहाँ परिभाषित ना हो कर सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) में परिभाषित हैं, का वही अभिप्राय होगा जो इनके लिए उक्त अधिनियम में दिया गया हो।

### 3. प्राधिकृत व्यक्ति को ईलेक्ट्रॉनिक इंटेग्रेटेड डिक्लेरेशन करना होगा. – प्राधिकृत व्यक्ति को—

(क) ईलेक्ट्रॉनिक इंटेग्रेटेड डिक्लेरेशन करना होगा और उसे ICEGATE पर अपना डिजिटल हस्ताक्षर करके समर्थनकारी दस्तावेजों को ICEGATE पर अपलोड करना होगा; या

(ख) ICEGATE पर ईलेक्ट्रॉनिक इंटेग्रेटेड डिक्लेरेशन करना होगा और साथ में सेवा केन्द्रों कि सहायता लेकर समर्थनकारी दस्तावेज़ भी अपलोड करना होगा।

**स्पष्टीकरण.**—इस विनियम के उद्देश्य से, अभिव्यक्ति “डिजिटल हस्ताक्षर” का वही अभिप्राय होगा जो इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) में दिया गया हो;

4. **शिपिंग बिल को जब दायर हुआ माना जाएगा और स्व:आंकलन को पूर्ण माना जाएगा.**— शिपिंग बिल को जब दायर हुआ माना जाएगा और स्व:आंकलन को तब पूरा माना जाएगा जब, ICEGATE पर ईलेक्ट्रॉनिक इंटेग्रेटेड डिक्लेरेशन किए जाने के पश्चात या सेवा केन्द्रों की सहायता से डाटा एंट्री किए जाने के बाद, उक्त घोषणा के उद्देश्य से इंडियन कस्टम्स ईलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज सिस्टम पर शिपिंग बिल की संख्या जनरेट हो गयी हो।

5. **धारा 51 या धारा 69 के अंतर्गत आदेश.** — आंकलन का काम पूरा हो जाने, शुल्क या उपकर आदि, यदि कोई हो, का भुगतान हो जाने और निर्यात माल की जांच हो जाने, यदि जरूरी हो, के पश्चात धारा 51 की उपधारा (1) या धारा 69, जैसी भी स्थिति हो, के अंतर्गत आदेश जारी करके, क्लियरेंस की अनुमति दी जाएगी और इस विनियम के अंतर्गत जारी होने वाले ऐसे आदेश को ICEGATE पर दर्ज किया जाएगा और इसको प्राधिकृत व्यक्ति, अभिरक्षी और अन्य कोई व्यक्ति जिसे की प्राधिकृत व्यक्ति नामित करे, को दे दिया जाएगा।

6. **शिपिंग बिल की आंकलित प्रति और समर्थनकारी दस्तावेजों को अपने पास रखना.** – प्राधिकृत व्यक्ति शिपिंग बिल के प्रस्तुत किए जाने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि तक, शिपिंग बिल की आंकलित प्रति, डिजिटल या अन्य किसी भी रूप में, और सभी समर्थनकारी दस्तावेजों को मूल रूप में रखेगा जो कि ईलेक्ट्रॉनिक इंटेग्रेटेड डिक्लेरेशन को किए जाने में उसके द्वारा प्रयुक्त किए गए थे या उनको आधार

बनाया गया था और वह उनको इस अधिनियम के अंतर्गत या तत्समय लागू किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत किसी भी प्रकार कि कार्यवाही या प्रक्रिया के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

7. **शिपिंग बिल की अभिप्रमाणित प्रति तैयार करना.** —प्राधिकृत व्यक्ति के अनुरोध पर शिपिंग बिल की एक अभिप्रमाणित प्रति तैयार की जा सकेगी यदि उक्त प्रति को तत्समय लागू किसी कानून के प्रावधानों के अनुपालन में उसके द्वारा रखना जरूरी हो।

8. **इन विनियमों के उल्लंघन आदि के लिए दंड.**—कोई भी प्राधिकृत व्यक्ति जो कि इन विनियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है या जो कि इन विनियमों के किसी भी प्रावधान का अनुपालन नहीं कर पाता है दंड का भागी होगा जो कि पचास हजार रुपए तक हो सकता है।

[फा. सं. 450/148/2015-सीमाशुल्क IV]

जुवैर रियाज़, निदेशक (सीमाशुल्क)

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 25th April, 2019

No. 33/2019-Customs (N.T.)

**G.S.R. 326(E).**—In exercise of the powers conferred by section 157 read with section 50 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of the Shipping Bill (Electronic Integration Declaration) Regulations, 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Board of Indirect Taxes and Customs, hereby makes the following regulations, namely:-

1. **Short title, application and commencement.**—(1) These regulations may be called the Shipping Bill (Electronic Integrated Declaration and Paperless Processing) Regulations, 2019.

(2) They shall apply to export of goods from all customs stations where the Indian Customs Electronic Data Interchange System is in operation.

(3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** – (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, -

(a) “Act” means the Customs Act, 1962 (52 of 1962);

(b) “authorised person” means an exporter or a person authorised by him who has a valid licence under the Customs Brokers Licensing Regulations, 2018 and includes an employee of the Customs broker who has been issued a photo identity card in Form G under the Customs Brokers Licensing Regulations, 2018;

(c) “electronic integrated declaration” means particulars relating to the export goods that are entered in the Indian Customs Electronic Data Interchange System;

(d) “ICEGATE” means the customs automated system of Central Board of Indirect Taxes and Customs;

(e) “section” means section of the Act;

(f) “service centre” means the place specified by the Principal Commissioner or the Commissioner of Customs, as the case may be, where the data entry of an electronic integrated declaration, is carried out;

(g) “shipping bill” means an electronic integrated declaration accepted and assigned a unique number by the Indian Customs Electronic Data Interchange System, and includes its electronic records or print outs.

**Explanation.** – For the purposes of this clause, the expression “electronic records” shall have the meaning assigned to it in the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);

(h) “supporting documents” means the documents in the electronic form or otherwise, which are relevant to the clearance of the export goods under sections 17 and 50 of the Act, respectively.

(2) Words and expressions used in these regulations and not defined but defined in the Customs Act, 1962 (52 of 1962) shall have the meanings as assigned to them in the said Act.

3. **Authorised person to enter, etc. electronic integrated declaration.** – The authorised person shall –

(a) enter the electronic integrated declaration and upload the supporting documents on the ICEGATE by affixing his digital signature on the ICEGATE; or

(b) get the electronic integrated declaration made on the ICEGATE along with the supporting documents by availing the services at the service centre.

**Explanation.** — For the purposes of this regulation, the expression “digital signature” shall have the meaning assigned to it in the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);

4. **Shipping bill when deemed to be filed and self assessment completed.** – The shipping bill shall be deemed to have been filed and self-assessment completed when, after entry of the electronic integrated declaration on the ICEGATE or by way of data entry through the service centre, a shipping bill number is generated by the Indian Customs Electronic Data Interchange System for the said declaration.

5. **Order under section 51 or section 69.** – After the completion of assessment, payment of duty or cess, etc. if any, and examination of export goods, if so required, an order permitting clearance, under sub-section (1) of section 51 or section 69 as the case may be, shall be made and the order under this regulation may be recorded on the ICEGATE and conveyed electronically to the authorised person, the custodian, and to any other person(s) designated by the authorised person.

6. **Retention of assessed copy of shipping bill and supporting documents.** – The authorised person shall retain, for a period of five years from the date of presentation of the shipping bill, the assessed copy of the shipping bill, digital or otherwise, and all supporting documents in original, which were used or relied upon by him in submitting the electronic integrated declaration, and shall produce them before Customs authorities in connection with any action or proceedings under the Act or under any other law for the time being in force.

7. **Generation of authenticated copy of shipping bill.** – An authenticated copy of shipping bill may be generated at the request of the authorised person if possession of the said copy is required by him for compliance of provisions of any law for the time being in force.

8. **Penalty for contravention, etc. of regulations.** – Any authorised person who contravenes any provision of these regulations or who fails to comply with any provisions of these regulations shall be liable to a penalty which may extend to fifty thousand rupees.

[F. No. 450/148/2015-Cus.-IV]

ZUBAIR RIAZ, Director (Customs)